# मासूम बच्चे की मैनहोल में मौत के जिम्मेदार हैं भ्रष्ट अधिकारी

**फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)** जिले के भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारियों की वजह से मैनहोल में गिरकर एक और मासूम बच्चे की मौत हो गई। शायद ही कोई ऐसा वर्ष बीतता हो जिसमें किसी न किसी की मैनहोल में गिरने से मौत न हुई हो। मासूमों की मौत के जिम्मेदार इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती इसलिए ये आम जनता की सुरक्षा के लिए मैनहोल के ढक्कन नहीं लगवाते जबकि मोटा कमीशन मिलने पर तो ये नए ढक्कन भी बदलवा देते हैं।

गरीब चाय विक्रेता विकास के साथ 18 जून की रात घर लौट रहे चार वर्षीय बेटे आनंद की सेक्टर 59 झाड़सेतली स्थित स्काईपैक नामक फैक्ट्री के पास खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। विकास कार्यों में लूट कमाई करने के लिए पूरे फरीदाबाद को अपने क्षेत्राधिकार में मानने वाले नगर निगम, हूडा, स्मार्ट सिटी और एफएमडीए के अधिकारी हादसे के बाद अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। नगर निगम के अधिकारियों ने तुरंत ही यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि घटना क्षेत्र

हूडा का है, उनका नहीं। जब बात कमीशनखोरी और काली कमाई की होती है तो यही अधिकारी हूडा के सेक्टरों में भी लाखों रुपयों के विकास कार्य स्वीकृत कर देते हैं। बच्चे की मौत पर हूडा अधिकारियों ने भी पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि सेक्टर एचएसआईआईडीसी को हस्तांतरित किया जा चुका है इसलिए वह घटना के जिम्मेदार नहीं हैं। उन्हें याद दिलाया गया कि सेक्टर की देखभाल और मरम्मत का जिम्मा तो अभी भी हुडा के पास ही है इस पर गोलमोल जवाब देते हुए वह एचएसआईआईडीसी की ही बात करते रहे। पुलिस तो इन अधिकारियों से भी आगे निकल गई। विकास का आरोप है कि पुलिस ने बेटे की हादसे में मौत होने की पहले से लिखी तहरीर पर उससे दस्तखत करा लिए जबकि वह इस मामले में स्काईपैक कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहता था। उसका आरोप था कि कंपनी के कर्मचारियों ने पानी का बहाव बनाए रखने के लिए जानबूझ कर मैनहोल का ढक्कन हटाया था। छोटे से छोटे निर्माण कार्य को सूंघते हुए मौके पर पहुंचने वाले हूडा और नगर निगम के अधिकारियों को यह खुला हुआ मैनहोल न दिखा हो मुमकिन नहीं लगता, हां विकास के इस आरोप से पुलिस की ठीकठाक दिहाड़ी बन गई होगी। सेक्टर 58 थाना इंचार्ज अनूप ने बताया कि परिवार वाले पहले तो आरोप लगा रहे थे लेकिन बाद में पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नजर आए। उनकी सहमित से सीआरपीसी की धारा 174 की कार्रवाई की गई।

## अपराध की रोकथाम नहीं, वसूली की कवायद है नाइट डोमिनेशन

**फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)** काम तो नहीं लेकिन काम का ढिंढोरा जोर से पीटने वाली भाजपा सरकार में पुलिस भी यही करने में जुट गई है। अपराधियों पर अंकुश लगाने के नाम पर हर महीने किसी एक रात को नाइट डोमिनेशन का ढिंढोरा पीटा जाता है लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चालक और वाहनों के चालान होते हैं। इस कवायद का फायदा आम जनता को तो क्या होता है लेकिन चालान के नाम पर अपने लिए और सरकार के लिए अच्छी खासी वसूली हो जाती है।

अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण की सरकार की मंशा के मुताबिक इस महीने भी 18 की रात को नाइट डोमिनेशन का ड्रामा किया गया। यानी इस रात सभी थानों की पुलिस, सीआईए, ट्रैफिक पुलिस सड़क पर उतर आई। आम रातों में नशा तस्कर, अवैध तमंचाधारी, हत्या आरोपी, जीएसटी चोरी का माल लाद कर जाने वाले वाहनों को पकड़ने वाली थानों की पुलिस और सीआईए को इस रात कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर बार इस विशेष अभियान में कोई अपराधी, चोर, अराजकतत्व पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। पकड़े कौन जाते हैं, इस रात किसी जरूरत या विशेष कारण से सड़क पर निकलने वाले आम नागरिक और उनके वाहन। इसके अलावा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चंद चालक। सड़क पर मुस्तैद पुलिस उनकी जांच कर कोई भी कमी पाए जाने पर तुरंत चालान थमा देती है, या वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। इन लोगों को अपराधी की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता। यानी कई सालों से चल रहे इस नाइट डोमिनेशन के ड्रामे में पुलिस किसी बड़े अपराधी या अपराध के नेटवर्क को नहीं पकड़ सकी है। आम दिनों में जो अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं वे खास कर इसी रात अंडरग्राउंड क्यों हो जाते हैं? इस रात जीएसटी चोरी गैंग के दागी ट्रक भी नहीं गुजरते, न ही कोई वाहन चोर, नशा तस्कर सड़क पर मिलता है। अवैध हथियार लेकर भी इस रात कोई अपराधी नहीं निकलता। लगता है उन्हें पहले से ही जानकारी हो जाती है कि आज नाइट डोमिनेशन है, उनके नहीं मिलने पर पुलिस को आम वाहन चालकों का चालान कर संतुष्ट होना पड़ता है। पुलिस मामलों के जानकार कहते हैं कि पुलिस का काम तो राज्य की कानून व्यवस्था संभालना है लेकिन सरकार अब इसका इस्तेमाल राजस्व वसूली के लिए कर रही है, पुलिस मुख्यालय से वाहनों के चालान, इंपाउंड आदि करने का बाकायदा टारगेट दिया जाता है ताकि जुर्माने के रूप में सरकारी खजाने में मोटी रकम जमा हो सके।

# फ़ासीवाद का एक जवाब, इंक़लाब जिंदाबाद

**क्रांतिकारी मज़दूर मोर्चा, हरियाणा**

मोदी सरकार, हर मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम रही है। पिछले 9 साल, देश के इतिहास में एक काले धब्बे की तरह नमूद होंग। रीढ़विहीन और दरबारी मीडिया के दम पर, योजनाबद्ध तरीके से फैलाई मज़हबी ख़ुमारी और अंधराष्ट्रवाद के नशे का शिकार होकर, झूठ और पाखंड पर भरोसा कर, 2014 में जिन लोगों ने झूमकर मोदी को वोट दिए थे वे सब आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बात सिर्फ़ चुनावी वादे पूरे करने की नहीं है, वे तो आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किए, न ही कोई पार्टी, पूंजी के मौजूदा निज़ाम को पलटे बगैर कर सकती है, वे तो किए ही लोगों को ठगने के लिए जाते हैं, लेकिन जिस निर्लज्जता से, भाजपा ने उन्हें अपने पैरों तले कुचला है, और जिस नंगई से उन्होंने अडानी-अम्बानियों की सेवा की है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा कर ठगा हो, वह 40 करोड़ बेरोज़गारों की विशाल फौज़ को 50,000 नोकारियों के नियुक्ति-पत्र देते हुए, शर्मिंदगी नहीं बल्कि गौरवान्वित महसूस करता हो, उसे क्या कहा जाए? उनके वादे याद दिलाने वालों को, मोदी सरकार, 'देशद्रोही' बताकर जेल में डाल देती ह। जो भी उनके झूठ, पाखंड और अडानी-अम्बानी की निर्लज्ज ताबेदारी पर सवाल करे, वह देशद्रोही है!!

असंख्य कैमरों और टेलीप्रोम्प्टर के सामने, हाथ लहराकर दहाड़ने वाले मोदी को, किसी ने मंहगाई पर बोलते सुना है क्या? आंकड़ों की बाजीगरी छोड़िये, बाज़ार क्या कहता है? हर वस्तु के दाम, हर माह बढ़ते जा रहे हैं, और वस्तुओं की मात्रा घटती जा रही है। क्या उसके अनुरूप, वेतन बढ़ रहे हैं? इस भारी-भरकम, संवेदनहीन तंत्र में, मेहनतकशों के दर्द को महसूस करने वाला, उनकी व्यथा सुनने वाला, कहीं कोई नज़र आता है क्या? मोदी सरकार ने, मज़दूरों पर सबसे घातक हमला, श्रम क़ानून लागू कराने के लिए जिम्मेदार इदारों, जैसे श्रम विभाग, भविष्यनिधि विभाग और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पूरी तरह ठप्प करके, बोला है। ये सब अधिकारी स्पष्ट बोलते हैं, कि उन्हें सरकार के लिखित आदेश हैं, कि मालिकों को मनमानी करने दो। ये विभाग पहले भी मालिकों की सेवा ही किया करते थे, लेकिन मज़दूर संगठनों के सक्रिय होने पर ऐसे मालिक के तो कान उमेठते ही थे, जो मज़दूरों का पीएफ और ईएसआईसी भी बेशर्मी से निगल रहा है। जो वेतन भी तय हुआ है, उसका भुगतान नहीं कर रहा। आज स्थिति इतनी भयावह है कि कारखाना मालिक, सालों साल काम कराते हैं, और मज़दूर वेतन मांगते हैं, तो उन्हें गन्दी गालियां देकर, पीटकर भगा देते हैं। पहले कभी ऐसा देखा है? 80 प्रतिशत मालिक ईएसआईसी की, मज़दूर से वसूली गई कटौती भी जमा नहीं कर रहे। दुर्घटना होने के बाद कार्ड बनाया जाता है। मोदी के इस अमृत काल में मज़दूर मरने के लिए आज़ाद है। कहने को लेबर कोड लागू नहीं हैं, लेकिन उनके लागू होने के बाद, मज़दूर जो शोषण झेलेंगे, उससे कहीं अधिक ज़ुल्म-ज़्यादती मज़दूरों को आज झेलनी पड़ रही है।

महिलाओं के सम्मान के बारे में मोदी सरकार, भाजपा और संघ परिवार के चरित्र के बारे में तो किसी को पहले से ही कोई संदेह नहीं रहा, लेकिन गुंडे-दबंग बृजभूषण सिंह वाले प्रकरण ने, इन लोगों का चाल-चरित्र-चेहरा एकदम नंगा करके रख दिया है। कोई भी बलात्कारी, लम्पट गुंडा, अगर चुनाव में भाजपा के किसी काम आ सकता है, तो वह कितनी भी गुंडई करे, कितना भी नंगा नाच करे, भाजपा को फ़र्क नहीं पड़ता। वह उसे बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। गुंडा-बलात्कारी- हत्यारा, अगर भाजपाई है तो वह संस्कारी है!! सारा देश,आज, अपने मान-मर्यादा की लड़ाई लड़ रहीं, बहादुर महिला खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन भाजपा, संघ कुनबा और सारे निठल्ले, मुफ़्तखोर भगवाधारी, तथाकथित साधू-संत, गुंडे-दबंग बृज भूषण के साथ है। कठुआ, हाथरस, उन्नाव, बिलकिस बानो और ना जाने कितने भगवाधारी लम्पटों-गुंडों-बलात्कारियों को भाजपाईयों ने ना सिर्फ़ क़ानून की गिरफ़्त से बचाया है बल्कि आम जन-मानस की भावनाओं, क्रोध को दरकिनार करते हुए, उन्हें सम्मानित भी किया है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई है। कितना भी छटा हुआ बदमाश, गले में भाजपा का पट्टा डालते ही संत हो जाता है। बृज भूषण को गिरफ़्तारी से जिस नंगई से बचाया गया, उसके बाद तो ऐसा माहौल पैदा होने का ख़तरा नज़र आने लगा है कि कोई सरकारी बाहुबली, किसी भी घर में घुसकर हमारी बहू-बेटियों के साथ कुछ भी कर सकता है। पुलिस उसके विरुद्ध कोई भी कारवाई करने से पहले मोदी सरकार क्या चाहती है, ये देखेगी।

देश में 85 करोड़ लोग कंगाली के उस स्तर पर कैसे पहुंच गए, कि दो जून रोटी के लिए, सरकारी खैरात के लिए, हाथ फैलाने की ज़िल्लत झेलने को मजबूर हैं? भूख सूचकांक में भारत, अपने पड़ोसी देशों से भी कहीं बदतर हालत में, सोमालिया के नज़दीक 107 वें नंबर पर कैसे पहुंच गया? क्यों, आज, तिहाई हाथों को काम नहीं है? क्यों सरकारी अस्पताल, कुत्तों के विश्राम स्थल बन गए और आधी से अधिक आबादी, किसी भी तरह का इलाज कराने लायक़ नहीं बची? देश में एक तरफ़ कंगाली का महासागर बन चुका है और दूसरी तरफ़, अडानी-अम्बानियों

की दौलत के पहाड़ विशाल होते जा रहे हैं; ऐसा क्यों और किस नियम के तहत हो रहा है? क्या मोदी सरकार के अजेंडे में कभी ये सवाल आते हैं? कभी इन विषयों पर कैबिनेट मीटिंग हुई? भाजपाई मीटिंगों का एजेंडा क्या होता है? किस मस्जिद के नीचे मंदिर होने के सबूत पैदा किए जाने की गुंजाइश है? स्कूल जाती बच्चियां हिज़ाब क्यों पहन रही हैं? 'गौ माता और गोवंश' का नाम लेकर, लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और मुस्लिम समाज को असली दुश्मन ठहराने के लिए कौन से हथकंडे अपनाए जा सकते हैं? वैज्ञानिक, तर्कपूर्ण समझदारी पैदा होने से रोकने और मज़हबी जहालत, आस्था आधारित दकियानूसी, सड़े-गले विचारों को प्रस्थापित करने और अंध भक्तों की फौज़ तैयार करने के लिए, इतिहास को कैसे विकृत किया जाए, शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कैसे किया जाए? मोदी सरकार ऐसा क्यों कर रही है, किस के हित में कर रही है, मेहनतक़श अवाम को क्यों बांटना चाहती है? मेहनतक़श अवाम क्या करे? ये जीवन-मरण के ऐसी गंभीर सवाल हैं जिन पर गंभीर विचार-मंथन करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

'धरमवार फ़साद ते ओन्हांदे इलाज़', जून 1927 में किरती में छपे अपने पंजाबी निबंध में, शहीद-ए- आज़म भगतसिंह लिखते हैं; "लोगों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए वर्ग-चेतना महत्वपूर्ण है। ग़रीब मज़दूरों और किसानों को यह स्पष्ट रूप से समझाना होगा, कि उनके असली दुश्मन पूंजीपति हैं, इसलिए उन्हें सावधान रहना चाहिए, कि वे उनके जाल में न फंसे। दुनिया के सभी गरीब लोगों को, उनकी जाति, नस्ल, धर्म या राष्ट्र कुछ भी हो, समान अधिकार हैं। यह आपके हित में है कि धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता के आधार पर सभी भेदभाव समाप्त करते हुए, राज-सत्ता अपने हाथ में ले लें। ऐसा करने से आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा बल्कि एक दिन आपकी बेड़ियां कट जाएंगी और आपको असली आर्थिक आजादी मिल जाएगी।"

1927 को, जब शहीद-ए-आज़म भगतसिंह द्वारा, इस रोग को पहचानकर सही इलाज बताया गया था, पूरे 96 साल बीत गए। जो भी कारण रहे, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि मज़दूर और मेहनतक़श किसान, पूंजीपतियों के राज़ को आज तक ख़त्म नहीं कर पाए। शासन की हर व्यवस्था, एक निश्चित ऐतिहासिक अवधि के बाद काल-बाह्य हो जाती है। पूंजीवाद की मुद्दत काफ़ी पहले पूरी हो चुकी। क्रांतिकारी शक्तियां, इसे उखाड़कर नहीं फेंक पाईं, परिणामस्वरूप ये सड़ने लगी है। जिन मान्यताओं और मूल्य बोध को पूंजीवाद ने ही कभी प्रस्थापित किया था, उन्हें ही आज ये खाती जा रही है। वह एक ऐसे संकट में फंस चुकी है, जिससे निकलने का हर उपाय उसे और गहरे गड्ढे में धकेल दे रहा है। अपनी अवश्यंभावी मौत के डर से, वह उत्पादक शक्तियों को ही नष्ट करने लगी है। उनमें फूट डालकर, आत्मघाती ख़ूनी जंग में झोंक देने पर उतारू है। समाज के कंगालीकरण के साथ-साथ, नशाखोरी, सांस्कृतिक सड़न, अश्लीलता और नैतिक पतन को योजनाबद्ध तरीक़े से बढ़ाया जा रहा है। चंद हाथों में सारी दौलत सिमट चुकी है, जिनकी ताबेदारी सरकार करती है। उसका चरित्र नंगा हो चुका। हुकूमत की मैलागाड़ी, अब बस दमन-चक्र और हिंसा के सहारे ही सरक रही है। इस हिंसा का शिकार, वह तबक़ा सबसे ज्यादा हो रहा है, जो कमज़ोर है, जिसे पूंजीवादी शोषण के अलावा, अतिरिक्त शोषण भी झेलना पड़ता है, जैसे महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी। शासन के इस स्वरूप को फ़ासीवाद कहते है। हमारे देश की सत्ता के चरित्र में आज फ़ासीवाद का हर लक्षण स्पष्ट नज़र आ रहा है।

पारोली, उत्तराखंड में, जून महीने में जो घटा, उसने साबित कर दिया कि संघ परिवार की हिमाक़त, नंगई और जुर्रत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। 'देवभूमि रक्षा अभियान' के नाम पर, इस असली 'टुकड़े- टुकड़े गैंग' द्वारा, मुस्लिमों की दुकानों पर क्रॉस लगाना और सारे के सारे मुस्लिम समाज को जेहादी बताकर, उन्हें उत्तराखंड से भाग जाने का अल्टीमेटम देना ठीक वैसा ही है, जैसे हिटलर के नाज़ी गैंग ने जर्मनी में यहूदियों के साथ किया था। उत्तराखंड सरकार और पुलिस, इन हिन्दुत्ववादी जेहादियों के विघटनकारी ज़हरीले अजेंडे को पहले भी मदद ही करते आए हैं। आज भी अगर सचेत नहीं हुए तो इतिहास हम सब को गुनहगार ठहराएगा। तीव्र जन-आक्रोश को भांपकर हिन्दुत्ववादी फासिस्टों की 15 और 20 जून को होने वाली महापंचायतों पर उत्तराखंड उच्च न्यायलय ने रोक लगा दी लेकिन इनमें से किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

चंद धन-पशु लुटेरों, गुंडों, बलात्कारियों की ताबेदार, भाजपा सरकार और उनका कुनबा, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं और ना इस देश की गंगा-जमुनी तहज़ीब का। इनका असल अजेंडा; भयंकर कंगाली, अभूतपूर्व बेरोज़गारी और बेइन्तेहा मंहगाई में पिसते जा रहे, मज़दूरों और मेहनतक़श किसानों की एकता को खंडित करना और उन्हें मज़हबी जहालत की अंधेरी कोठरी में धकेलकर, सारा देश, अडानी-अम्बानियों को अर्पित करना है। इस प्रक्रिया में देश अगर टूटता है, तो भी इन्हें परवाह नहीं। फ़ासीवादी हमला दिनोंदिन तीखा होता जा रहा है। मार्टिन निमोलर की वह कालजयी सीख हमारे सामने है। ये 'इंडियन नाज़ी', एक-एक कर, हर तबक़े को निशाने पर लेने वाले हैं। बदक़िस्मती से, हमारे देश की अदालतें भी इन्हें रोकने में नाकाम रही हैं।

सर्वोच्च अदालत, संविधान की रक्षक है; ऐसा मात्र दिखना चाहती है, उसके लिए कोई भी कड़ा, निर्णायक क़दम लेने से बचती आई है। फ़ासिस्ट गिरोह का हौसला, अदालतों की इन्हीं नाकामियों ने बढ़ाया है। 'नरसंहार' का खुला आह्वान करने वाले, आज जेलों में नहीं बल्कि अपने अड्डों पर, ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि अपने काम में लगे हुए हैं। इस ख़ूनी तमाशे को चुपचाप बैठकर देखना या आँखें फेर लेना, अक्षम्य अपराध होगा।

दंगाईयों और उन्मादियों की इस पैदल सेना के आक़ाओं को पहचानकर, निशाने पर लेना होगा। प्रख्यात राजनीतिक विचारक, रजनी पाम दत्त ने फ़ासीवाद की कार्यपद्धति का विश्लेषण करते हुए लिखा है। "चीखते-चिल्लाते, बौखलाए, गुंडों, शैतानों और हठधर्मियों की यह फौज, जो फ़ासीवाद के ऊपरी आवरण का निर्माण करती है, इसके पीछे वित्तीय पूंजीवाद के अगुवा बैठे हैं, जो बहुत शांत भाव, स्पष्ट सोच और होशियारी से इस फौज का संचालन करते हैं और इनका ख़र्च उठाते हैं। फ़ासीवाद के शोर-शराबे और मनगढ़ंत विचारधारा की जगह, उसके पीछे काम करने वाली यही प्रणाली हमारी चिंता का विषय है और इसकी विचारधारा को लेकर जो भारी-भरकम बातें कही जा रही हैं उनका महत्त्व पहली बात, यानी घनघोर संकट की स्थितियों में कमजोर होते पूंजीवाद को टिकाए रखने की असली कार्यप्रणाली के सन्दर्भ में ही है।"

फ़ासीवाद, सड़ता हुआ पूंजीवाद है। पिसते, कराहते लोगों की ज़ुबान पर ताला लगाया जा रहा है। ख़तरनाक कानूनों को और ख़तरनाक बनाया जा रहा है। मेहनतक़श अवाम के सामने एक ही रास्ता है। सभी इंसाफ़ पसंद, प्रगतिशील, जनवादी एवं वामपंथी क्रांतिकारी शक्तियों को गोलबंद करते हुए, देशभर में, मज़दूरों और मेहनतक़श किसानों को, फ़ासीवाद-विरोधी जन आन्दोलनों की प्रचंड लहर खड़ी करनी होगी। मौजूदा वक़्त, हर जागरुक नागरिक और सभी क्रांतिकारी संगठनों से, बिना वक़्त गंवाए, सड़कों पर आने की मांग कर रहा है।